

'संविधान हत्या दिवस' पर संगोष्ठी

लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष था आपातकाल के खिलाफ लड़ाई



हमारा स्वराज। भोपाल

देश में आपातकाल लागू होने की 50 वीं वर्षगांठ को बुधवार को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 'आपातकाल विभीषिका' विषय पर संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी।

उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायालयों के फैसलों को पलट दिया गया। आपातकाल देश के लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान था। उन्होंने कहा कि आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को जिन लोगों ने देश में आपात काल लागू किया था, वे ही इस कलंक के लिए जिम्मेदार हैं और वे कभी भी इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, सांसद शंकर लालवानी, विधायक अजय विश्नोई, महेंद्र हाईडिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी। उस दौर में हजारों निरपराध लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। आपातकाल में लोगों पर

आपातकाल के बाद ही लागू हुआ वास्तविक लोकतंत्र: सुधांशु

राज्यसभा सांसद त्रिवेदी ने कहा कि आपातकाल में विधायिका, कार्यपालिका और न्याय-पालिका के साथ साथ मीडिया पर भी नियंत्रण लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि देश में वास्तविक लोकतंत्र आपातकाल की समाप्ति के बाद ही लागू हुआ है। राज्यसभा सांसद त्रिवेदी ने कहा कि देश में वैचारिक स्वतंत्रता पाने की लड़ाई आज भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हमें "आत्म गौरव" का आभास होने लगा है। श्री त्रिवेदी

ने कहा कि लोकतंत्र हमारे देश में 1947 से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व से लागू रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, साथ ही "लोकतंत्र की जननी" भी है। पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई ने आपातकाल में अपनी जेल यात्रा के अनुभव सुनाए। उन्होंने बताया कि 25 जून की रात में ही देश में सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

बेईतहा अत्याचार किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के योगदान का स्मरण भी किया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई देश की आजादी की दूसरी लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान किसी की भी संपत्ति जप्त की जा सकती थी। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था तथा संसद की बैठक के लिए कोरम की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी।

बुजुर्ग अब चुनौती
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के योगदान का स्मरण भी किया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई देश की आजादी की दूसरी लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान किसी की भी संपत्ति जप्त की जा सकती थी। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था तथा संसद की बैठक के लिए कोरम की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी।

अशोकनगर में कथित मल खिलाने के मामले ने पकड़ा तूल पुलिस ने बताया बेबुनियाद, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

हमारा स्वराज। अशोकनगर

अशोकनगर जिले के मुंगावली थाना क्षेत्र के बरवाय मुंडरा गांव में गजराज लोधी नाम के युवक को कथित रूप से मल (गंदगी) खिलाने के मामले ने जहां राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, वहीं पुलिस प्रशासन ने आरोपों को असत्य और बेबुनियाद करार देते हुए तथ्यों सहित खंडन किया है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग की है, जबकि अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह का कहना कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की तथ्यात्मक जांच करा कर कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को गजराज लोधी और उसके भाई रघुराज लोधी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी से भोपाल में मिले और पूरी आपबीती बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच और अन्य लोगों ने राशन पच्ची को लेकर विवाद में मारपीट की और गंदगी खिलाई। गजराज का कहना है



जीतू पटवारी से मुलाकात करते कथित पीड़ित।

मामला राहुल गांधी तक पहुंचा

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जीतू पटवारी ने मौके से ही अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह से फोन पर बात की और तत्काल कार्रवाई की मांग की। पटवारी ने कहा कि "किसी को मल खिलाना जघन्य अपराध है। यदि आठ दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं स्वयं गांव आकर आंदोलन करूंगा। राहुल गांधी तक यह मामला पहुंच चुका है, उन्होंने भी चिंता जताई है।" पटवारी ने इसे मानवता से जुड़ा मामला बताया, ना कि किसी जाति या दल से जुड़ा मुद्दा।

कि थाने में शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया और उन्हें भगा दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सरपंच रविन्द्र लोधी और

भाजपा नेता राजेश लोधी ने बाद में धमकाकर एक वीडियो बनवाया जिसमें गजराज को कहना पड़ा कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई।

पुलिस का खंडन: 'आरोप असत्य और मनगढ़ंत', वायरल वीडियो से मामला उलझा

इस पूरे मामले में अशोकनगर पुलिस ने आरोपों को पूरी तरह असत्य और तथ्यहीन बताया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने कहा, "10 अप्रैल को ग्राम मुंडरा निवासी विकास यादव ने डायल-100 पर शिकायत की थी कि एक व्यक्ति शराब पीकर उदरगत मचा रहा है और पत्थर फेंक रहा है। डायल-100 की टीम गजराज लोधी को थाने लाई।" उन्होंने बताया कि गजराज के भाई रघुराज लोधी ने एसडीओपी मुंगावली से संपर्क किया, उन्होंने तस्दीक कर रघुराज को सूचना दी कि उसके भाई गजराज के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। एसपी जैन ने बताया कि तब गजराज नशे में होने के कारण ठीक से चल और बोल नहीं पा रहा था। थाने पहुंची



उसकी मां के साथ घर भेज दिया गया था। एसपी जैन ने कहा कि उस दिन और न ही बाद में गजराज एवं उसके परिजनों में से किसी ने भी मल खिलाने का कोई जिक्र नहीं किया था। 10 जून को गजराज द्वारा जनसुनवाई में कलेक्टर को दी गई शिकायत में भी ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया था। एसपी

जैन ने बताया कि गजराज द्वारा जनसुनवाई में राशन पच्ची नहीं दिए जाने की शिकायत की जांच ADM और CEO जिला पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि गजराज द्वारा पात्रता पच्ची न मिलने का आरोप भी असत्य था। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि "एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें गजराज का भाई रघुराज, विकास यादव से कह रहा है कि 25 लाख रुपये दो, नहीं तो मैं यह मामला आगे बढ़ाऊंगा। इसमें विकास यादव कहता है कि किस बात के 25 लाख दूं? और दे भी दूं, तो क्या गारंटी है?" एसपी ने इस वीडियो को मामले को नया मोड़ देने वाला करार देते हुए कहा कि इसकी विधिवत जांच की जा रही है।

कलेक्टर का बयान: 'हर पहलू की होगी जांच, नियमानुसार कार्रवाई होगी'

इस मामले पर अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि "मामले के सभी पक्षों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राहत और बचाव का सिलसिला जारी

एमपी में सुरंग ढही, धर्मशाला में लैंडस्लाइड, अब तक 4 की मौत

हमारा स्वराज। भोपाल

बुधवार को दो बड़े हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। पहली घटना मध्यप्रदेश के महु में सामने आई है। महु के पास इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाइवे पर चोरल में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई।

हादसा बुधवार सुबह करीब 4 बजे हुआ। पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। उन्होंने प्राथमिक तौर पर इसकी वजह बारिश को बताया गया है। झारखंड निवासी विकास राय (29) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सिंगरौली निवासी लालजी कौल (26) ने इंदौर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार के मुताबिक, हादसा इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूर चोरल इलाके में टनल नंबर 3 में हुआ। इसका काम हैदराबाद की मेधा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। बुधवार तड़के टनल का करीब 18 मीटर ऊंचा और 16 मीटर चौड़ा हिस्सा नीचे गिर पड़ा। सुरंग ढहने से जान गंवाने वाला विकास राय झारखंड में गिरिडीह जिले के झोंका वर्मासिया का रहने वाला था। शव पोस्टमॉर्टम के लिए इंदौर के जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं, लालजी कौल को गंभीर रूप से घायल होने के बाद था। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।



हृदय विदारक घटना

मृतक विकास के जीजा और प्रत्यक्षदर्शी सुदामा सिंह के मुताबिक, रात 3.30 से 4.00 बजे के बीच टनल के ऊपर से पत्थर और मिट्टी गिरने से घटना हुई। हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। पत्थर गिरने से एक लडका वहीं गाड़ी में चिपक गया था। वह गाड़ी में खड़ा होकर काम कर रहा था। हादसे में वह गाड़ी पर ही चिपका रह गया। हम लोग 8 दिन पहले ही यहां काम करने आए थे। मृतक विकास मेरा साला था।

कुल्लू में 3 जगह बादल फटा, पिता-बेटी समेत 3 बहे; लैंडस्लाइड से आदिकैलाश का रास्ता बंद

हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बुधवार को तेज बारिश हुई। खनियारा इलाके के सोकणी दा कोट में ईंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15-20 मजदूर मनुणी खड्ड (नदी) में बह गए। अबतक दो मजदूरों के शव मिले हैं।

मनुणी नदी आम दिनों में सूखी ही रहती है, लेकिन तेज बारिश के कारण नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। मजदूर नदी किनारे बने शेड में रह रहे थे। इसलिए बाढ़ की चपेट में आ गए। कुल्लू जिले में भी 3 जगह सैज घाटी के जीवा नाला, गढ़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटा। जीवा नाला में बाप-बेटी समेत 3 लोग बह गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचुला-लिपुलेख रोड पर लैंडस्लाइड हुआ। इसके कारण



आदिकैलाश रोड बंद हो गया। दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। हल्द्वानी में एक कार नहर में गिर गई। कार सवार 7 लोगों में से 4 की मौत हो गई। इनमें तीन दिन का बच्चा भी शामिल है। केरल के वायनाड के आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। चूरलमाला में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले साल मुडक्कई, चूरलमाला,

अडमाला समेत दूसरे इलाकों में लैंडस्लाइड में 369 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू में मंगलवार रात हुई भारी बारिश के चलते तवी नदी उफान पर है। इसमें एक शख्स फंस गया। SDRF के लोगों ने सीढ़ी के सहारे उसका रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी तेज बारिश का अलर्ट है।

ट्रम्प को फरवरी में हमले का प्लान बताया

नई दिल्ली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि उन्होंने फरवरी में व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान पर हमले का प्लान बता दिया था। नेतन्याहू ने यरुशलम में कैबिनेट मीटिंग से पहले कहा, 'मैंने हमले का दो प्लान शेयर किया था। एक अमेरिका के साथ और

दूसरा अमेरिका के बिना। मैंने साथ देने या न देने का फैसला ट्रम्प पर छोड़ा था।' दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नीदरलैंड में नाटो समिट में मीडिया से कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के कारण 12 दिनों तक चली ईरान-इजराइल जंग रुकी। उन्होंने कहा, '12 दिनों के दौरान ईरान नर्क से गुजरा।

अंतरिक्ष पहुंचकर एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले- व्हाट ए राइड



नई दिल्ली। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सिसम मिशन 4 के तहत आज यानी, 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनका ये मिशन पहले 6 बार तकनीकी दिक्कतों के कारण टल चुका था। उनके साथ तीन अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद शुभांशु ने कहा- व्हाट ए राइड। मेरे कंधे पर लगा तिरंगा बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। वहीं लॉन्चिंग सफल होने पर शुभांशु के माता-पिता आशा शुक्ला और शंभु दयाल शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने बेटे की सफलता पर ताली बजाकर खुशी जताई। मिशन भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12:00 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 267वीं बैठक

नर्मदा घाटी परियोजनाओं के संचालन में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाए

हमारा स्वराज । भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नर्मदा नदी राज्य की जीवनदायिनी है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित गतिविधियों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे और ऊर्जा उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है जिसके चलते प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के अंतर्गत निर्मित सिंचाई व्यवस्था में सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। जल उद्‍घन में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने से बिजली पर होने वाले व्यय में कमी लाई जा सकेगी। किसानों को भी सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। मां नर्मदा के जल का प्रदेश हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 267वीं बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संपन्न हुई। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, मनीष रस्तोगी सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में शहीद ईलाप सिंह

माईक्रो उद्घन सिंचाई परियोजना जिला हरदा, सेंधवा माईक्रो उद्घन सिंचाई परियोजना जिला बड़वानी, निवाली उद्घन सिंचाई परियोजना जिला बड़वानी, धार उद्घन माईक्रो सिंचाई परियोजना, माँ रेवा उद्घन सिंचाई परियोजना जिला देवास की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिए गए। बैठक में

निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही डोबी सिंचाई परियोजना, भीकनगांव बिजलवाडा माईक्रो सिंचाई परियोजना, आई.एस.पी.-पार्वती लिंक परियोजना, खालवा उद्घन माईक्रो सिंचाई परियोजना जिला खण्डवा की समयवृद्धि प्रस्ताव पर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मोरंड गंजाल बांध एवं दाबयुक्त सिंचाई परियोजना के निर्माण में आईएसपी जलाशय और अपर नर्मदा परियोजना के कमाण्ड में निर्माण कार्य आरंभ करने के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में विजयराघवगढ़ उद्घन माईक्रो सिंचाई परियोजना, गुनौर माईक्रो सिंचाई परियोजना, झिरन्या एक्सटेंशन (विस्तार) माईक्रो उद्घन सिंचाई परियोजना, बड़ादेव चरगंवा सूक्ष्म उद्घन सिंचाई परियोजना, खेड़ी बुजुर्ग उद्घन माईक्रो सिंचाई परियोजना जिला धार की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में नर्मदा नदी के धार्मिक एवं सामाजिक और पर्यटन महत्व के स्थलों पर घाट निर्माण के संबंध में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।

कतर से मनीषा की सकुशल स्वदेश वापसी

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल कर कुशलक्षेम जानी



हमारा स्वराज । भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इजरायल-ईरान युद्ध के चलते कतर से वापसी के लिये रह गई उज्जैन निवासी मनीषा भटनागर की सकुशल स्वदेश वापसी के बाद उनसे वीडियो कॉल पर चर्चा कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उल्लेखनीय है कि मनीषा भटनागर

कतर एयरवेज में सीनियर केबिन क्रु हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उनकी सकुशल वापसी के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सहयोग के लिए अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को केंद्र सरकार के संपर्क में रहते हुए मनीषा की सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने की 3,756 पदों पर भर्ती, पांज हजार 317 पदों के लिए 61 भर्ती प्रक्रिया जारी

हमारा स्वराज । भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में अब तक मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने 3 हजार 756 पदों पर भर्ती की है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा ने बताया कि दिसम्बर 2023 से अब तक जारी 75 विज्ञापनों में शामिल 4 हजार 492 पदों के लिये 3 हजार 756 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसा पत्र भेजे गये हैं। आयोग ने 81 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। इनके माध्यम से आगामी महिनो में 5 हजार 562 पद भरे जाएंगे। वर्तमान में 5 हजार 317 पदों के लिए 61 भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। आयोग जारी किये गए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उपर्युक्त सभी परिणाम मध्यप्रदेश शासन एवं उच्च न्यायालय के कुल विज्ञापित पदों में से 87% पदों के परिणाम घोषित करने के निर्देशों के अनुपालन में घोषित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि एक संस्था के रूप में मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने प्रतिष्ठित सरकारी भूमिकाओं के लिए सबसे उपयुक्त और प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान कर उनका चयन किया और राज्य की सेवा के प्रति अपने समर्पण को लगातार प्रदर्शित किया है। आयोग ने ऐसा करके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सार्थक योगदान दिया है। इस तरह आयोग ने एक सक्षम और कुशल राज्य प्रशासन की आधारशिला के रूप में अपनी भूमिका को पुष्ट किया है। आयोग के सचिव प्रबल सिपाहा ने बताया कि आयोग द्वारा उक्त अवधि में 3 राज्य सेवा परीक्षा - 2019, 2021, 2022 के लिए 1,109 पदों और 3 राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए 200 पदों के लिए अंतिम चयन परिणाम घोषित किए गए। संबंधित विभागों को संस्तुतियां शीघ्र भेजी गईं, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में शीघ्र कार्यभार ग्रहण कराने में सुविधा हुई। उपर्युक्त अवधि में राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग

को क्रमशः 72 डिप्टी कलेक्टर एवं 51 उप पुलिस अधीक्षक के पदों के लिए संस्तुतियां भेजी गईं। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के माध्यम से सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के 132 पदों तथा मप्र वित्त सेवा के 22 पदों के लिए भी स्कूल शिक्षा एवं वित्त विभाग को संस्तुतियां की गईं। राज्य वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के 19 तथा वन क्षेत्रपाल एवं परियोजना क्षेत्र अधिकारी के 181 पदों के लिए वन विभाग को अनुशंसा पत्र भेजे गए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में रेडियोलॉजी विशेषज्ञ के 7 पदों के लिए अनुशंसा भेजी गई। आयुष विभाग के लिए 17 विषयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 543 तथा आयुष व्याख्याता के 71 पदों के लिए विभाग को अनुशंसा की गई। उच्च शिक्षा विभाग को सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के अंतर्गत 25 विषयों के 727 पदों के लिए अनुशंसा की गई।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी प्राथमिक

जिम्मेदारी मध्यप्रदेश राज्य की विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश सरकार के लगभग 48 सरकारी विभागों द्वारा एक अनिवार्य और कठोर प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर, मध्यप्रदेश सरकार के 55 जिलों और विभिन्न विभागों में सेवारत सभी राजपत्रित अधिकारियों का चयन किसी न किसी समय मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से हुआ है। विगत कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की उपलब्धियाँ वास्तव में सराहनीय रही हैं। आयोग द्वारा जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों की संख्या, आयोजित परीक्षाएँ, घोषित परिणाम और उसके बाद नियुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर की गई सिफारिशों ने अगले तीन से चार दशकों के लिए राज्य के विभागों की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भोपाल में बीजेपी ऑफिस में बनाई प्रतीकात्मक जेल

आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान पीछे लिए इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाई

हमारा स्वराज । भोपाल

25 जून को देश में आपातकाल लगे 50 साल पूरे हो गए । 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। ऐसे में बीजेपी ने आज के दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में आयोजन प्रदेशभर में किया। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रतीकात्मक जेल बनाई गई है। बीजेपी ऑफिस में बनाई गई प्रतीकात्मक जेल के सामने इंदिरा गांधी की फोटो लगाई है। इस फोटो में इंदिरा गांधी संविधान को अपने हाथों में पीछे छिपाए हुए नजर आ रही हैं। दूसरे तरफ लिखा है- कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय का 50वां वर्ष। **संविधान संशोधन की जानकारी दी गई** : बीजेपी कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आपातकाल के दौरान किए गए संविधान संशोधनों को समझाया गया है। **38वां संशोधन** : इसके पोस्टर में बताया गया है, सत्ता को जवाबदेही से मुक्त करने की चाल.... आपातकाल और राष्ट्रपति के फैसलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया। घोषित आपातकाल को अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया। कार्यपालिका को अदालती निगरानी से पूरी तरह मुक्त किया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की न्यायिक रक्षा की संभारना भी खत्म कर दी गई। **39वां संशोधन** : इस संशोधन में प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से



बाहर किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटकर इंदिरा गांधी का चुनाव बचाने के लिए रातों-रात पारित किया गया। **6 अगस्त, बुधवार**: संशोधन लोकसभा में पेश किया गया। **7 अगस्त, गुरुवार**: अगले ही दिन पारित भी कर दिया गया।

8 अगस्त, शुक्रवार: एक दिन के भीतर ही राज्यसभा में पारित कर दिया गया। **9 अगस्त, शनिवार**: कांग्रेस शासित राज्यों में विशेष सत्र बुलाकर जरूरी 50% विधानसभाओं से अनुमोदन प्राप्त किए गए। **10 अगस्त, रविवार**: संशोधन को अंतिम

रूप देने के लिए रविवार को भी राष्ट्रपति भवन खुला रहा।

बीजेपी नेताओं आपबीती सुनाई

प्रदर्शनी में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आपातकाल में किए गए दुर्व्यवहार और जेल के अनुभवों को बताते हुए पोस्टर लगाए गए हैं।

सिंधिया ने शेयर किया राजमाता सिंधिया के आपातकाल का वीडियो

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- मेरी पूज्य आजी अम्मा, श्रद्धेय राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी ने राजपथ को त्याग कर लोकपथ की राह चुनी थी। लोकतंत्र और जनसेवा के प्रति उनकी निष्ठा ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। आपातकाल के दिनों में भी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें कई तरह की यातनाएं दी और अत्याचार किए। उनको जेल में भी डाला गया - लेकिन वे न झुकीं, न दर्बीं और न टूटीं। लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के सम्मान के लिए वह अडिग रहें। उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचार हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।

आपातकाल की घोषणा की 50वीं बरसी पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश

लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीसाबंदियों का संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों जैसा

हमारा स्वराज । भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश में आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं बरसी पर कहा है कि गणतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने आपातकाल के संघर्ष में कुर्बानी दी है। इसी का प्रतिफल है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सुरक्षित है। भारत में संघ परिवार ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा श्रद्धेय मोरारजी देसाई सहित विपक्ष के सभी नेताओं ने एक स्वर में आपातकाल का विरोध करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

यह स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। इसीलिए सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी नाम मिला है। उन्होंने कहा कि एशिया में लोकतंत्र कहीं बचा है तो उसमें जनता पार्टी सहित विपक्षी नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उल्लेखनीय है कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन माना जाता है।

एम्स भोपाल में कैसर मरीजों को जल्द मिलेगी दो बड़ी सुविधाएं

गामा नाइफ यूनिट और पेट स्कैन होगा शुरू

हमारा स्वराज । भोपाल

राजधानी स्थित एम्स लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में अब यहां आने वाले कैसर मरीजों के लिए दो बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। जिनमें से प्रमुख है गामा नाइफ यूनिट और पेट स्कैन जांच दोनों ही सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। गामा नाइफ यूनिट में मस्तिष्क में पनप रहे कैसर का त्वरित इलाज हो सकेगा। इस तकनीक से ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैसर, ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया और एकोस्टिक न्यूरोमा जैसी बीमारियों का सटीक इलाज किया जा सकता है। वही पेट स्कैन शुरू होने से 20 हजार तक की महंगी जांच सरलता से हो पाएगी। पेट स्कैन जांच की सुविधा मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं है।

अब तक देश में केवल चार संस्थानों में है या सुविधा : एम्स भोपाल में बन रही गामा नाइफ यूनिट की लागत लगभग 85 करोड़ रुपए आएगी। देश में अब तक सिर्फ चार संस्थानों में ही यह तकनीक है। गामा नाइफ से इन्फेक्शन रेंडियस मात्र 0.01 फीसदी ही रह जाता है। यही नहीं इससे 0.1 एमएम के क्षेत्र में भी रेंडिएशन दिया जा सकता है। इसमें ब्रेन की खून ले जाने वाली शिरा को छेड़े बिना सीधे ट्यूमर के डीएनए को नष्ट करता है। इस मशीन को इंस्टॉल

करने के जरूरी बंकर अक्टूबर तक तैयार होंगे।

गामा नाइफ एक अत्याधुनिक तकनीक

एम्स के डायरेक्टर डॉ. अजय सिंह ने बताया कि गामा नाइफ एक अत्याधुनिक तकनीक है। केंद्र सरकार के उपक्रम हाइस्ट्रस द्वारा इसे खरीदा जा रहा है। बंकर का निर्माण भी सीपीडब्ल्यूडी कर रहा है। काम 50 फीसदी हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि गामा नाइफ के लिए रेंडिएशन प्री बंकर बनाने के लिए जिम्मेदारी सीपीडब्ल्यूडी को दी गई थी, लेकिन, काम की रफ्तार धीमी होने के कारण अब यह काम एचएलएल जांच प्रोटेक्ट सर्विसेस लिमिटेड को दिया गया है।

20 हजार में होती है पेट स्कैन की जांच : कैसर के ज्यादातर मरीजों को पेट स्कैन की जांच करानी पड़ती है। यह जांच काफी महंगी होती है। यह जांच भोपाल में लगभग 18 से 20 हजार में निजी अस्पतालों में की जाती है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्स भोपाल में जल्द ही यह जांच शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पेट स्कैन शुरू करने की तैयारी अंतिम पड़ाव पर है।

फिर भी भारत बेटों पर मोहित

देशकाल-परिस्थितियों और बदलती जरूरतों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर एक सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बदलाव लिंग प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में आ रहे परिवर्तन का है। जैसा कि हाल ही में ‘द इकनॉमिस्ट’ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कों के प्रति सदियों पुराना झुकाव अब कम हो रहा है। दुनियाभर में, अतिरिक्त पुरुष जन्म की संख्या- जो वर्ष 2000 में 1.7 मिलियन तक अधिक थी, साल 2025 तक लगभग दो लाख तक गिर गई है। निस्संदेह, यह प्रजनन विकल्पों में एक अप्रत्याशित बदलावों का संकेत है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बदलाव की असल वजह क्या है दरअसल, माता-पिता में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि बेटियां उनकी ढलती उम्र में धीरे-धीरे अधिक विश्वसनीय देखभाल करने वाली साबित हो सकती हैं। उन्हें परिवार से गहरे तक जुड़े रहने की अधिक संभावना के रूप में देखा जाने लगा है। आज बेटियों को बेटों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शनकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। तेजी से कामकाजी दुनिया का हिस्सा बनने के कारण वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती जा रही है। बल्कि कई देशों में तो महिलाओं की बैचलर डिग्री की संख्या तक पुरुषों की तुलना में अधिक है। पश्चिमी देशों में गोद लेने और आईवीएफ के डेटा दिखाते हैं कि बेटियों को चुनने की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। दरअसल, पश्चिमी देशों के एकल परिवारों में बेटे अपनी गृहस्थी बसाकर मां-बाप को उनके भाग्य पर छोड़ जाते हैं। ऐसा माना जाने लगा है कि बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में मां-बाप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। जिसके चलते लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को अपनी प्राथमिकता बनाने को तरजीह देने लगे हैं। वहीं भारत में परिस्थितियां एक जटिल तसवीर प्रस्तुत करती हैं। यूं तो सदियों से भारत का समाज पुत्र मोह की ग्रंथि से ग्रस्त रहा है। हालांकि, अब आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में शिशु लिंग अनुपात दर में सुधार हुआ है। लेकिन लिंग चयन के लिये किए जाने वाले गर्भपात पर शासन व प्रशासन की कानूनी सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद परंपरागत रूप से समाज में गहरी जड़ें जमाने वाला बेटा मोह अब भी प्राथमिकता बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5(2019-21) का सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। सर्वे के अनुसार, लगभग 15 फीसदी भारतीय माता-पिता अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों की आकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा,पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विषम शिशु लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा, भारत में बेटी वरीयता, जहां यह मौजूद है, अक्सर सशर्त होती है।

हमले से बढ़ा वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा

गत सप्ताहांत अमेरिकी वायु सेना के बी-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमानों ने ईरान के उन तीन ठिकानों पर हमले किए जो परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित हैं। फोर्दों, नतांज और इस्फहान नामक इन शहरों में ये परमाणु ठिकाने जमीन के बहुत नीचे स्थित हैं और इसलिए अधिकांश हमलों से सुरक्षित भी हैं। गत सप्ताह जब इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू किए तो यह माना जा रहा था कि जमीन के भीतर दबी ये परमाणु इकाइयां सुरक्षित हैं। केवल अमेरिकी बंकर बस्टर बम (जीबीयू-57) ही 60 मीटर की गहराई पर स्थित इन ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। इस बात की काफी अटकलें थीं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प इजरायल के लगातार अनुरोधों

पर आगे बढ़ेंगे और वह करने की कोशिश करेंगे जो उसके हवाई हमले नहीं कर सके। उन्होंने अपने चुनावी वादे में कहा था कि वह अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं शामिल करेंगे लेकिन उन्होंने ईरान पर बमबारी को लेकर भी सकारात्मक रुख दर्शाते हुए कहा है कि अमेरिका लंबे समय से ईरान को लेकर नरमी बरत रहा है। उनका यह बयान खासतौर पर परमाणु प्रतिबंध समझौते को लेकर रहा जिसे उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आगे बढ़ाया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक दशक पीछे धकेलने जैसा वांछित परिणाम हासिल हुआ है अथवा नहीं। संवर्धित यूरेनियम की जिस छोटी सी मात्रा के लिए तथा और अधिक यूरेनियम संवर्धन

की संभावना के चलते ये हमले किए थे, संभव है कि उसे पहले ही किसी नए ठिकाने पर पहुंचाया जा चुका हो, जो हमले से दूर हो। चाहे जो भी हो अगर ईरान की क्षमताओं को नियंत्रित करना प्राथमिकता थी तो भी ऐसे हमले को शायद ही जरूरी माना जा सकता हो। जंगी परमाणु हथियार के तत्त्व तैयार करना एक बात है और उसे इस तरह तैयार करना कि उसे मिसाइल के जरिये हमले में इस्तेमाल किया जा सके एकदम दूसरी बात है। इजरायल सार्वजनिक और निजी रूप से लंबे समय से यह कहता आ रहा है कि ईरान कुछ ही महीने में अपना परमाणु कार्यक्रम पूरा कर सकता है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस मौके पर अमेरिका एक बेलगाम महाशक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है।

आपातकाल: स्वर्णिम लोकतंत्र का काला अध्याय

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान लोकतंत्र का रक्षक, क्योंकि संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की आधारशिला है, किंतु 25 जून 1975 से 31 मार्च 1977 तक का कालखंड ऐसा था, जब देश में सत्ताधारी नेताओं द्वारा इन सभी मूल्यों का गला घोंटा गया। संवैधानिक शब्दावली में इस कालखंड को आपातकाल कहा गया परंतु इतिहास में इसे ‘स्वर्णिम लोकतंत्र के काले अध्याय’ के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए न केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को स्थगित करके भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर भी कुठाराघात किया।

1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ के नारे पर भारी बहुमत से चुनाव अवश्य जीता, लेकिन 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली से उनके निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया और 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिये भी अयोग्य ठहरा दिया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पद को खतरे में डाल दिया। अपनी सत्ता को बचाने की लाचारी और राजनीतिक वर्चस्व की भूख ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का यह निर्णय किसी राष्ट्रीय संकट के कारण नहीं बल्कि श्रीमती गांधी की सत्ता लोलुपता से प्रेरित था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर उन्होंने देश को आपातकाल के अंधकार में धकेल दिया।

संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश में आपातकाल मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाना चाहिए, परंतु श्रीमती गांधी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 26 जून 1975 को सुबह 6:00 केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर मंत्रियों को बताया कि मध्यरात्रि के बाद से देश में आपातकाल लगा दिया गया है। कुल मिलाकर देश में आपातकाल लागू करने के बाद और देश को यह सूचना देने से पहले श्रीमती गांधी ने मंत्रिमंडल की महज औपचारिक सहमति प्राप्त की, जो उनकी तानाशाही को दर्शाता है। आपातकाल लागू करते ही इंदिरा गांधी की तानाशाही शुरू हो गई। उन्होंने देश में नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया।

श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्र वादी विचारधारा को कुचलने का कार्य किया। लोकतंत्र को बचाने के लिये प्रतिरोध करने वालों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये। जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े नेताओं को गिरफ्तार कर ‘मीसा’ अर्थात आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेई और लालकृष्ण आडवाणी जैसे अनेक वरिष्ठ नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक बिना सुनवाई के लगभग 01 लाख 40 हजार से अधिक लोगों को जेल में बंदकर दिया गया। लोकतंत्र की सबसे जरूरी विशेषता ‘वैकल्पिक विचार’ को श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजद्रोह में बदल दिया।

आपातकाल में इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका जो लोकतंत्र की रक्षा की अंतिम संस्था है, उसे भी झुकने पर मजबूर कर दिया। न्यायपालिका की स्वायत्तता को छीन ने का प्रयास किया गया। सत्ता की आलोचना करने वाले अखबारों को सेंसर कर दिया गया। अनेक समाचार पत्रों के छपने पर रोक लगा दी गई।यह प्रेस की स्वतंत्रता का सबसे भयावह क्षण था। संजय गांधी के मार्गदर्शन में चलाए जाने वाला ‘नसबंदी अभियान’ सरकारी

आतंक का प्रतीक बन गया। व्यक्तिगत सत्ता स्थायित्व के लिए संविधान में प्रजातंत्र विरोधी संशोधन किए गए। न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की गई। यह वास्तव में भारत के लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ने की एक बड़ी सजिश थी। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने ‘इंदिरा इज इण्डिया एण्ड इण्डिया इज इंदिरा’ जैसे नारों को प्रसारित किया जो इंदिरा गांधी की निरंकुशता, तानाशाही और संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं। आपातकाल के दौरान प्रसिद्ध कवि जी.एस. शिवरूद्रप्पा ने ‘इस देश में’ नामक एक कविता लिखी-

इस देश में
वीर पूजा, परिवार पूजा
खत्म होनी चाहिए,
लेकिन मेरी कुल देवी की तरफ कोई आंख न उठाए,
इस देश में
हर एक को अपना मुंह बंद रखना चाहिए
लेकिन उन्हें मेरे शब्द सुनने के लिए
अपने कान खुले रखना चाहिए

यह कविता देश में इंदिरा गांधी की तानाशाही और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों पर किए गए वज्रपात को प्रदर्शित करतीहै। आजकल कुछ विपक्षी नेता संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर रसंद से सड़कों तक ‘संविधान खतरे में है’ और ‘लोकतंत्र खतरे में है’ के नारे लगा रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले इन नेताओं को थोड़ा अतीत में झांकना चाहिए।राहुल गांधी को पीछे जाकर अपनी दादी इंदिरा के काले कारनामों को देखना चाहिए, कि किस तरह उनकी सत्ता की लालसा ने देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की हत्या की थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश विकास और प्रगति के नए आयाम को स्पर्श कर रहा है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। समावेशी विकास में लोकतंत्र की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास को प्रवाहित किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला और जनधन जैसी योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संवैधानिक मूल्यों और प्रावधानों के अनुक्रम में धारा 370 को हटाने, जीएसटी लागू करने जैसे राष्ट्रीय हित के कार्यों को मूल रूप प्रदान किया है। आपातकाल लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है, जो हमें चेतावनी देताहै, कि सत्ता का केंद्रीकरण किस हद तक लोक स्वतंत्रता को कुचल सकता है।

आपातकाल इस बात की चेतावनी है, कि जब सत्ता की भूख विवेक पर हावी हो जाती है, तब लोकतंत्र खोखला हो जाता है। इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया आपातकाल उनके राजनीतिक स्वार्थ और आत्ममुग्धता का प्रतीक था। वह एक समय था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की आत्मा को कुचलकर सत्ता की कुर्सी को बचाया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके देश की जनता पर जो अत्याचार किया, उसका उत्तर जनता ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके दिया। जिससे यह स्पष्ट है कि आपातकाल भारत के स्वर्णिम लोकतंत्र में न केवल एक काला अध्याय है, बल्कि सत्ता के मद में चूर श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही का भी प्रतीक है।

कड़वाहट से मुक्ति के लिये सम्मानजनक अलगाव

आज के बदलते सामाजिक परिवेश में, जहां रिश्ते जटिल होते जा रहे हैं, तलाक एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। भारत में तलाक की प्रक्रिया अक्सर लंबी, तनावपूर्ण और आरोप-प्रत्यारोप से भरी होती है। यह न केवल पति-पत्नी बल्कि उनके बच्चों और परिवारों के लिए भी भावनात्मक और आर्थिक बोझ बन जाती है। पारंपरिक तलाक कानूनों में, तलाक तभी दिया जाता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर ‘गलती’ (जैसे व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग) साबित करे। इसमें अक्सर एक लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई शामिल होती है, जिसमें दोनों पक्षों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने पड़ते हैं, जिससे कड़वाहट और दुश्मनी बढ़ती है। इसके विपरीत, ‘नो-फॉल्ट’ तलाक में, तलाक के लिए किसी भी पक्ष को दूसरे की गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बेवफाई, क्रूरता या परित्याग जैसे विशिष्ट कारणों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो दोनों पक्षों को सम्मानपूर्वक अलग होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका मुख्य आधार ‘अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका विवाह’ होता है। ऐसे में, विकसित देशों के अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां ‘नो-फॉल्ट’ तलाक एक

सफल मॉडल साबित हुआ है। विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में ‘नो-फॉल्ट’ तलाक ने कई सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। सबसे पहले, इसने तलाक की प्रक्रिया को काफी सरल और तेज बना दिया है। अदालती कार्यवाही कम होती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। दूसरा, यह प्रक्रिया को कम विरोधी बनाता है। जब किसी एक पक्ष पर दोष नहीं लगाया जाता, तो कटुता और प्रतिशोध की भावना कम होती है, जिससे बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनता है और भविष्य में सह-पालन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, यह महिलाओं को सशक्त बनाता है। पारंपरिक तलाक कानूनों में अक्सर महिलाओं को अपनी स्थिति साबित करने के लिए अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन ‘नो-फॉल्ट’ तलाक उन्हें इस बोझ से मुक्त करता है। भारत में वर्तमान में तलाक के लिए विभिन्न आधार उपलब्ध हैं और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक (धारा 13 बी) शामिल हैं। आपसी सहमति से तलाक ‘नो-फॉल्ट’ सिद्धांत के करीब है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें और प्रतीक्षा अवधि शामिल है। भारत में तलाक से संबंधित मौजूदा कानून, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, अभी भी काफी हद तक ‘फॉल्ट-आधारित’ है।



एसडीएम ने किया ग्राम चुरारी एवं निदानपुर नल-जल योजना का निरीक्षण देखी हर घर जल की जमीनी हकीकत



हमारा स्वराज। चंदेरी

कलेक्टर के आदेशानुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंचायतों को हस्तांतरित नल जल योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा ग्राम निदानपुर एवं ग्राम चुरारी की नल जल योजनाओं का निरीक्षण किया गया। एसडीएम द्वारा निरीक्षण के दौरान योजना के समस्त अवयवों की जानकारी ली गई तथा योजना से लाभान्वित सभी ग्राम वासियों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि

ग्राम में नियमित रूप से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय करें। साथ ही ग्राम वासियों से पानी की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। भ्रमण के दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि समय समय पर पानी को उबालकर पीने एवं पानी की जांच करने के साथ-साथ पानी के उपचार करने की समझाइस दी। भ्रमण के दौरान तहसीलदार दिलीप दरोगा, प्रभारी सहायक यंत्री पीएचई धर्मान्शु दीक्षित, विकास खंड समन्वयक अविनाश गौस्वामी व ग्राम के सरपंच और सचिव उपस्थित रहे।

सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

विधायक हरिबाबू ने किया ग्रामों का भ्रमण



हमारा स्वराज। अशोकनगर

विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरि बाबू राय गत दिवस अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से जाना। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके से ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। सबसे पहले विधायक ग्राम काकाखेड़ी पहुंचे, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर बिजली से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर ही विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात वे

विजयपुरा ग्राम पहुंचे, जहाँ उन्होंने समस्त ग्रामवासियों के साथ मिलकर डीपी के लिए उपयुक्त स्थान का जायजा लिया और जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया। अपने दौरे के अंतिम चरण में वे झीला ग्राम पहुंचे, जहाँ उन्होंने पूरे गाँव का भ्रमण किया तथा स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क और कृषि से जुड़ी चुनौतियों को भी साझा किया। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासित किया कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वे हरसंभव प्रयास करेंगे और शासन-प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई कराएंगे।

राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने लगाया आपातकाल: बिरथरे

अशोकनगर। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने, सत्ता पर काबिज रहने और प्रजातंत्र को कुचलने के लिए देश में आपातकाल लगाया 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लागू गए आपातकाल की 50वीं बरसी पर बुधवार को स्थानीय अग्रवाल पैलेस में भाजपा द्वारा पत्रकार वार्ता, संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आपातकाल को काला दिवस बताते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया गया। पत्रकार वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नरेंद्र बिरथरे, भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी,

नगर पालिका अध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी नीरज मनोरिया,चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, जिला महामंत्री रविंद्र लोधी,जिला मीडिया प्रभारी डॉ हरवीर सिंह रघुवंशी तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे ने आपातकाल को कांग्रेस का राष्ट्र और संविधान विरोधी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपने पद को बचाने के लिए देशभर में आपातकाल थोप दिया, जिसके तहत करीब 1 लाख 40 हजार लोगों को जेल में डाला गया। श्री बिरथरे ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए संविधान का दुरुपयोग करते हुए 39वां संशोधन किया।

निरीक्षण: आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को मीनू अनुसार नहीं मिल पा रहा था भोजन

कलेक्टर ने दिए स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष को हटाने के निर्देश

हमारा स्वराज। अशोकनगर

कलेक्टर आदित्य सिंह ने बुधवार को अशोकनगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा कर आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और प्रसिद्ध करीला धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर कई अधिकारियों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने सबसे पहले मुंगावली तहसील के ग्राम मल्हारगढ़ का भ्रमण किया। यहां उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1, 2, 3 और 4 का निरीक्षण किया और बच्चों की जानकारी, वजन पंजी तथा हाइट पंजी का अवलोकन किया। कुपोषित बच्चों और नाश्ते व भोजन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। बच्चों को मेनू के अनुसार नाश्ता और भोजन न देने पर दुर्गा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष को हटाने के निर्देश दिए गए। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 03 की खराब हालत को देखते हुए उसे दूसरी जगह स्थानांतरित करने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायत को दिए गए। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 01 में शौचालय न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव निरंजन सिंह राजपूत की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों द्वारा पानी की समस्या बताए जाने पर कलेक्टर ने रोजगार सहायक पद्म सिंह का 15 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। मल्हारगढ़ में ही उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कक्षों में पंजियों का अवलोकन किया और नर्सिंग स्टॉफ बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। आयुर्वेदिक औषधालय में अनुपस्थित पाए गए डॉ. मनोज श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से मुलाकात



मां जानकी धाम परिसर भी पहुंचे कलेक्टर

कलेक्टर सिंह ने अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां जानकी माता मंदिर करीला धाम का निरीक्षण किया। मंदिर परिसर में पर्याप्त साफ-सफाई न मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि करीला धाम परिसर में समुचित साफ-सफाई बनी रहे। साफ-सफाई की कमी पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगावली आलोक इटोरिया को कारण बताओ नोटिस और ग्राम पंचायत सचिव अरविंद सिंह यादव की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सीता रसोई की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। नृत्यांगनाओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने और करीला मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। मंदिर में प्रसादी चढ़ाने के लिए अगरबत्ती और नारियल हेतु जगह चिन्हित कर स्टैंड बनाने के निर्देश भी दिए गए। इस निरीक्षण के दौरान मुंगावली एसडीएम मनोष धनगर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आलोक इटोरिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कर बिजली, सड़क और पानी सहित मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को

आवश्यक निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान, कलेक्टर आदित्य सिंह ने मुंगावली सिविल अस्पताल का



आंगनबाड़ी में कराएं नल कनेक्शन

इसके बाद, कलेक्टर सिंह ने ग्राम बिल्हेरू का दौरा किया। यहां उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 103 का निरीक्षण किया। बच्चों को समय पर नाश्ता और भोजन न मिलने पर देविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कुपोषित बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की जानकारी ली और बच्चों की उपस्थिति, हाइट पंजी व वजन पंजी का अवलोकन किया। आंगनवाड़ी केंद्र में नल कनेक्शन कराने के निर्देश भी दिए गए। बिल्हेरू में ही शासकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करते हुए उन्होंने मध्याह्न भोजन के किचन शेड का अवलोकन किया और प्रवेशोत्सव व पुस्तकों के वितरण संबंधी जानकारी ली।

भी विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और चल रहे मरम्मत कार्य के संबंध में एसडीएम मुंगावली को आवश्यक निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया और पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण करते हुए मरीजों के नमूनों

की जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एनआरसी वार्ड के भ्रमण के दौरान कुपोषित बच्चों का कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में अनुपस्थित पाए गए अकाउंटेंट गोपाल गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

'एक दिन का विधायक'-पिछोर में लोकतंत्र की अनोखी मिसाल

हमारा स्वराज। पिछोर

जहां राजनीति अकसर सत्ता, शक्ति और प्रोटोकॉल के इर्द-गिर्द घूमती है, वहीं मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। यहां लोकतंत्र का ऐसा प्रयोग हो रहा है, जो न सिर्फ अनोखा है, बल्कि प्रेरणादायक भी। इस प्रयोग का नाम है – 'एक दिन का विधायक'। यह पहल किसी और ने नहीं, खुद क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने शुरू की है। उनके अनुसार, लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव



जोतकर कुर्सी पर बैठ जाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाना है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक संकल्प लिया – हर

दिन एक आम आदमी विधायक बने और जनसुनवाई करें। पिछोर के सरकारी रेस्ट हाउस में रोज सुबह एक अनोखी तस्वीर देखने को मिलती है।

वहां दो कुर्सियां होती हैं – एक पर बैठते हैं प्रीतम सिंह लोधी, और दूसरी पर बैठता है उस दिन का 'एक दिन का विधायक'। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है – एक किसान, मजदूर, महिला, युवा, छात्र या व्यापारी। उस आम नागरिक को न सिर्फ बैठने की जगह दी जाती है, बल्कि वह पूरे आत्मसम्मान के साथ जनता की समस्याएं सुनता है, सुझाव देता है और उन्हें हल करने के लिए आदेश जैसी भूमिका में होता है। विधायक लोधी इस प्रक्रिया में सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। वे कहते हैं,

‘जब तक जनता खुद नेतृत्व का अनुभव नहीं करेगी, तब तक लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा।' यह नवाचार न सिर्फ प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पारदर्शी बना रहा है, बल्कि आमजन को यह एहसास भी करा रहा है कि वे सिर्फ वोटर नहीं हैं – वे भी शासन का हिस्सा हैं। 'एक दिन का विधायक' योजना की गुंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी है। कई जगहों से सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और राजनेता इस पहल को देखने पिछोर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी खूब सराहना हो रही है।

सकवारा विद्यालय भवन मिला जर्जर हालत में पंचायत भवन में लगेगा स्कूल

एसडीएम ने किया निरीक्षण, लिया मध्यान भोजन का स्वाद

हमारा स्वराज। चंदेरी

चंदेरी एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी निरंतर शासकीय विभागों का निरीक्षण कर रही है। लगातार शासकीय कार्यों में कसावट लाने के साथ जन समुदाय को उचित और समय पर व्यवस्थित प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाए इसी दृष्टिकोण को रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ने किया।

इस दौरान तहसीलदार दिलीप दरोगा, बीईओ राजेश तिवारी, बीआरसीसी वेद प्रकाश गोयल मौजूद रहे। पीएम श्री हाई स्कूल प्राणपुर का निरीक्षण किया गया जिसमें निरीक्षण के दौरान विद्यालय से संबंध सभी



व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं। जहां पर अनुविभागीय अधिकारी ने स्कूल में अध्यनरत बच्चों के साथ मध्यान भोजन भी किया जबकि प्राथमिक विद्यालय नानकपुर की बिल्डिंग जीर्ण सीर्ण अवस्था में पाई गई जिसे देख एसडीएम ने तत्काल मरम्मत के निर्देश

बीआरसी को दिए प्राथमिक विद्यालय सकवारा की बिल्डिंग का निरीक्षण करने के दौरान विद्यालय का भवन अत्यधिक स्थिति में जर्जर और किसी भी समय गिरने की स्थिति में मिला है, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल उक्त भवन में स्कूल न लगाने का आदेश

गुणवत्ता में आएगा सुधार:

अनुविभागीय अधिकारी अथवा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण लगातार किए जाने के कारण स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा

स्टाफ की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित होगी स्कूल बिल्डिंगों की जर्जर हालत और उनके रंग रोगन तथा मूलभूत सुविधाएं जो छात्र-छात्राओं को मिलना चाहिए उन सभी व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा।

मौके पर ही संबंधित विद्यालय की प्राचार्य सिया कुमारी को दिया गया। अब विद्यालय को पंचायत भवन में लगाया जाएगा। इस विद्यालय में मीनू के अनुसार मध्यान भोजन का वितरण भी नहीं मिला जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त कर मीनू अनुसार विद्यार्थियों को मध्यान भोजन वितरण करने की निर्देश दिए तथा मध्यान

भोजन वितरित करने वाले समूह को नोटिस जारी करने के निर्देश बीआरसी को दिए गए चुरारी विद्यालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ लोगों ने विद्यालय प्रांगण में अतिक्रमण कर लिया है उसे भी तत्काल हटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए इस दौरान विद्यालयों से संबंधित प्राचार्य उपस्थित रहे।